फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 299 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 31 मई, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

Ustadji Of Heeramandi

For my role as *Ustaad ji* in *Heeramandi*, I already knew Urdu since my father and mother's family had migrated from Lahore and Rawalpindi in Pakistan. So, I was well-versed with the pronunciations and the little nuances of the language.

Are You Also A Lychee Lover?

मनमोहन सिंह ने तीन पेज का खुला पत्र लिखा पंजाब के मतदान से पूर्व

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्र.मंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि, उन्होंने पंजाब, पंजाबी व पंजाबियत के आत्म सम्मान को कुचलने की हर संभव लगातार कोशिश की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 मई। शनिवार एक जून को सातवें चरण की वोटिंग से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक भावनात्मक अपील जारी की और मतदाताओं से कहा कि लोकतंत्र और संविधान को मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा बार-बार किए जा रहे प्रहारों से बचाने का यह आखिरी मौका है।

तीन पेज के खुले पत्र में डॉ. मनमोहन सिंह ने गत दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था मे हुई कल्पना से परे उथल पुथल और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नीत नैशनल डैमोक्रेटिक एलायंस की गलत नीतियों पर चिंता जताई।

पंजाब, जहां एक जून को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, के संदर्भ में डॉ. सिंह ने किसान आंदोलन का जिक्र किया व कहा कि किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने के लिए। डॉ. सिंह ने पंजाबियत को बदनाम करने के लिए सरकार की आलोचना की।

- **डॉ. मनमोहन सिंह ने किसान आंदोलन की याद दिलायी और कहा कि, सैकड़ों किसानों की जान गयी पुलिस फायरिंग से, पर शायद प्र.मंत्री मोदी किसानों पर गोली चलवाकर संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने संसद में किसान आंदोलनकारियों को ''पैरासाइट'' (जोंक) कहा।**
- **डॉ. मनमोहन सिंह ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अपने पत्र में यह भी लिखा कि, किसानों की प्रतिदिन आय 27 रू. ही है, जबकि हर किसान पर ऋण 27,000 रू. है।**
- **डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार भाजपा शासन में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट (जी.डी.पी.) 6 प्रतिशत से भी कम रही है। जबकि यू.पी.ए. सरकार में 8.5 प्रतिशत थी।**
- **डा. सिंह के अनुसार मोदी सरकार के शासन के दौरान, निर्धन व धनाढ्य की आय में अन्तर इतना बढ़ा है, जो गत 100 साल में नहीं था।**

उन्होंने कहा कि, लाठी और रबर बुलैट्स ही पर्याप्त नहीं थी, प्रधानमंत्री ने तो संसद के पटल पर किसानों को ''परजीवी'' तक कह कर बदनाम किया।

डॉ. सिंह ने कहा, मोदी जी ने 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था पर उनकी नीतियों की वहज से दस साल में आय कम हो गई है। किसान की राष्ट्रीय स्तर पर औसत आय मात्र 27 रू. प्रतिदिन है और वहीं हरेक किसान पर औसतन 27,000 रू. का कर्ज है। (यह सरकारी आंकडें हैं।)

पूर्व प्रधानमंत्री ने यू.पी.ए. सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का उल्लेख किया व कहा कि उन्होंने एम.एस.पी. में वृद्धि की और उत्पादन बढ़ाया तथा निर्यात को भी प्रोस्साहन दिया।

उन्होंने कहा, आज कांग्रेस ने एम.एस.पी. की लीगल गारंटी दी है जो कि आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग रही है। कांग्रेस ने कृषि के लिए स्थायी आयात-निर्यात नीति बनाने, कर्ज काफी और फसल के नुकसान पर बीमा की राशि 30 दिन के अंदर खाते में ट्रांसफर करने की गारंटी भी दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने विवादास्पद अग्निवीर योजना के लिए भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का वादा है कि अगर वह चुनाव जीती तो इस योजना को खत्म कर देगी।

उन्होंने कहा कि ''भाजपा सरकार ने सशस्त्र बलों पर अग्निवीर योजना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल ट्रायल कोर्ट पहुंचे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 मई। 30 मई को दिल्ली की राउज़ एवैन्यू कोर्ट कॉम्पलेक्स में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की बैंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को एक नोटिस जारी किया। केजरीवाल की दो में से एक याचिका नियमित जमानत दिए जाने तथा दूसरी

- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इन्कार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की है।**

अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने को लेकर दाखिल की गई थी। कोर्ट अब इस मामले पर आगामी सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे करेगा।

विधि विशेषज्ञों की राय है कि केजरीवाल के पास ट्रायल कोर्ट में जाने का सर्वश्रेष्ठ विधिक विकल्प उपलब्ध है ताकि न्यायिक हिरासत से बाहर रहने की अवधि का विस्तार करा सके। दिल्ली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा के शुभेन्दु अधिकारी चुनाव आयुक्त से मिले: पुलिस की ज्यादतियों की शिकायत दर्ज करायी

शिकायत के अनुसार भाजपा के 50 वरिष्ठ नेता गिरफ्तार किये गये, शुक्रवार को और 300 भाजपा समर्थकों व नेताओं के घर पर पुलिस ने छापे मारे

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 मई। तृणमूल कांग्रेस में हताशा बढ़ती जा रही है और वह अपने राज्य की पुलिस का खुलेआम दुरूपयोग कर रही है।

बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी गुरूवार को चुनाव आयुक्त से मिले और वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर निशाना साधकर की जा रही पुलिस कार्यवाही के संबंध में शिकायत दर्ज की। उन्होंने शिकायत की कि, कम से कम पचास भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के कम से कम 300 घरों पर छापा मारा गया है।

अधिकारी ने शिकायत की कि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य पुलिस ने सातवें चरण के लिये नियुक्त भाजपा के मतगणना और बूथ एजेंटों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि, राज्य पुलिस, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

एक व्यक्ति, जिसको चुनावी हिंसा के दौरान तृणमूल समर्थकों ने बुरी तरह मारा पीटा था, के विरूद्ध अब कई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **झरग्राम सीट पर भाजपा के उम्मीदवार पर, पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया।**
- **पुलिस मु.मंत्री कार्यालय के निर्देश पर भाजपा के उन कार्यकर्ताओं व नेताओं का नाम पता मांग रही है, जो पोलिंग बूथ पर बैठेंगे तथा मतगणना के समय उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होंगे।**

चुनावी उत्तेजना के बीच, ई.डी., बंगाल में एक बार फिर सक्रिय हो गयी है।

खास बात यह है कि, ई.डी. ने एक प्रमुख बंगाली अभिनेत्री को अपने ऑफिस में बुलाया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, बड़े पैमाने पर हुए राशन सप्लाई घोटाले से संबंधित कुछ ''मनी ट्रेल'' के बारे में उनसे पूछा गया है। रितुपर्णा सेनगुप्ता, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेत्री हैं और सिनेमा देखने वालों के लिए मुख्य आकर्षण हैं, को कोलकाता के ई.डी. ऑफिस में कुछ कागजातों के साथ बुलाया गया है।

मुद्दा यह है कि, गबन करे हुए धन को कहाँ निवेश किया या खपाया गया है। पूर्व पुलिस अफसरों का मानना है कि, इस तरह का बेहिसाब और गबन किया हुआ धन फिल्मों में और कुछ अन्य गतिविधियों में लगाया जाता है। सूत्रों के अनुसार, इन्हीं मनी ट्रेल्स के संबंध में रितुपर्णा सेनगुप्ता से पूछताछ करी जा रही थी।

'नये मकान मालिक से पुराने का बकाया बिजली बिल वसूलना विद्युत निगम की खराब कार्यप्रणाली को दर्शाता है'

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब निगम ने नये मकान मालिक के पक्ष में बिजली कनेक्शन जारी करने पर यह शर्त लगाई कि, वह पुराने मकान मालिक का 5.50 लाख रुपये का बिल चुकाये

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 30 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैशाली नगर में रहने वाले दम्पती के पक्ष में फैसला देते हुए राजस्थान विद्युत वितरण निगम को आदेश दिये हैं कि वह उनके पक्ष में तीन दिन में अस्थाई बिजली कनेक्शन जारी करे और यह शर्त ना लगाये कि यह दम्पती पहले मकान में रह रहे पुराने निवासियों का बकाया बिल चुकाए। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अस्थाई कनेक्शन जारी रहेगा कि नहीं, वह इस मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश रमेश चंद्र अग्रवाल व उनकी पत्नी सुमनलता अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए।

मामले के तथ्यों के अनुसार 4 सितम्बर 2023 को याचिकाकर्ताओं ने पुराने मकान मालिक से यह मकान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **अदालत ने इस तथ्य पर हैरानी जताई कि, बिजली विभाग ने मूल किरायेदार का बिजली कनेक्शन तो जारी कर दिया पर यह भी नहीं देखा कि उसका चैक बैंक द्वारा स्वीकार किया भी जायेगा या नहीं।**
- **अदालत ने इस पर आशंका जताई कि, विभाग ने दो साल तक एक भी बिल जारी नहीं किया और अदालत ने कहा कि, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि, विभाग ने दोषी पुराने किरायेदार के पक्ष में इतनी उदारता क्यों बरती।**
- **अदालत ने यह भी कहा कि, जब 2023 में पुराने मकान मालिक का भी चैक बाउंस हो गया था तो उन्होंने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की और अपनी पत्रावली में बिजली कनेक्शन का ''अकाउंट क्लोज़्ड'' क्यों दर्शाया। अदालत ने कहा कि, इन सभी तथ्यों से निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।**

बेंगलुरू जी.पी.ओ. में महिलाओं की भारी भीड़

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 मई। बंगलौर में महिलाएं शहर के जनरल पोस्ट आफिस पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बाहर कतार लगा रही हैं, ताकि उनके खाते खुल जाएं। उन्हें उम्मीद है कि, अगर केन्द्र में सरकार बदली और कांग्रेस

- **बताया जाता है कि, कांग्रेस के कुछ लोगों ने केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में प्रति माह 8500 रू. जमा करवाने की अफवाह उड़ा दी है, इसलिए महिलाएं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने पर आमादा हैं।**

नेतृत्व वाली सरकार आई तो उन्हें प्रति माह 8500 रू. मिलेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गत एक सप्ताह में सैकड़ों महिलाओं ने खाते खुलवाए हैं क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'लू और तापघात से मरने वाले लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा दें'

हाई कोर्ट ने प्रदेश में भारी गर्मी के कारण चल रही लू और हीट स्ट्रोक की भयावह स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को गाइड लाइन जारी की

जयपुर, 30 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्तमान भारी गर्मी के कारण उत्पन्न लू और तापघात की स्थिति को देखते हुए आठ मुख्य दिशा निर्देश दिए हैं जिनमें मुख्य तौर पर कहा गया है कि सरकार लू से मरने वालों के आश्रितों को उचित मुआवजा दे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सरकार खुले में काम करने वाले कामगारों, जैसे कुली, रिक्शा और बैलगाड़ी चलाने वाले तथा अन्य समूहों के लिये दिशा निर्देश जारी करे कि वे 12 से 3 बजे के बीच कार्य ना करें बल्कि छाया में विश्राम करें। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिये हैं कि वे लू से पीड़ित मरीजों के लिये सभी तरह की सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर मुहैया कराएं।

जस्टिस अनूप ढंड ने प्रकरण पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव व गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे हर विभाग के

- **हाई कोर्ट ने खुले में काम करने वाले कामगारों, जैसे, कुली, रिक्शा चालकों, मजदूरों आदि के लिए भी दोपहर12 से 3 बजे तक काम नहीं करने व छांव में विश्राम करने का निर्देश दिया।**
- **हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द ही ''हीट एक्शन प्लान'' लागू करने को भी कहा है।**
- **ज्ञातव्य है कि, लू और शीतलहर से मौत के बचाव को लेकर राज्यसभा में बिल पेश किया गया था, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी अब तक यह संसद से पारित होकर कानून नहीं बन सका है।**
- **अदालत ने कहा कि, अब वक्त आ गया है कि, लू और शीतलहर से बचाव के प्रावधानों को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए।**

ए.सी.एस. या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में विभागों की समिति बनाए। यह कमेटी राजस्थान क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत 'हीट एक्शन प्लान' (एच.ए.पी.) और वृक्षारोपण, जल, वन और बिजली संरक्षण के लिए बनाई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर एक 'हीट एक्शन प्लान' तैयार किया था। इस प्लान के अनुसार श्रेणीवार तापमान के अनुसार ग्रेडिंग की गई थी। इस ग्रेडिंग के अनुसार 43-44.9 डिग्री तापमान होने पर 'हीट अलर्ट' घोषित की जायेगी और 45 डिग्री से ऊपर 'एक्सट्रीम हीट अलर्ट' दी जायेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्लान को जल्द से जल्द लागू किया जाये।

अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि वह प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए खंडपीठ के समक्ष एक जुलाई को मामला सूचीबद्ध करें। अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, चिकित्सा व परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्रम व उद्योग विभाग, नागरिक व आपूर्ति विभाग, राज्य के मुख्य सचिव, मौसम विभाग के सचिव, ए.सी.एस. होम, राज्य के आपदा प्रबंधन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद को बधाई दी

जयपुर, 30 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट ''नॉर्वे चेस-2024'' में लीडर्स पोज़ीशन हासिल करने पर भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अठारह वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश

- **18 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद वर्ल्ड नम्बर वन, मैगनस कार्लसन को हराकर विजेता बने हैं।**

बाबू प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर वन मैगनस कार्लसन को हराकर यह विजय प्राप्त की है। शर्मा ने कहा कि, प्रज्ञानंद की यह ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने प्रज्ञानंद के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

धौलपुर के राजीविका मॉडल से जुड़ीं पश्चिम अफ्रीका की महिलाएं

गुरूवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अभय कुमार ने माली और सेनेगल से प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं से संवाद किया

जयपुर, 30 मई। राजस्थान के धौलपुर जिले का राजीविका मॉडल पश्चिम अफ्रीकी देशों, सेनेगल एवं माली में 12500 महिलाओं की आजीविका का साधन बना है। धौलपुर की राजीविका महिलाओं ने सेनेगल एवं माली देशों में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने, ग्राम संगठन एवं फेडरेशन बनाने का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद फेडरेशन को संचालित करने की पद्धित एवं विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया और आज इन देशों की महिलाएँ वर्षभर में करीब 17 करोड़ की बचत करती हैं और उसी बचत से इंटर लोनिंग कर अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं तथा एवं प्रशिक्षण के द्वारा नए-नए कार्य कर रही हैं।

गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार ने इंदिरा गांधी नहर मंडल में पश्चिम अफ्रीकी देश माली और सेनेगल से राजस्थान में प्रशिक्षण के लिए आए प्रतिनिधियों के साथ आगे के सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधियों ने राजीविका के माध्यम से मिल रहे सहयोग के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। दोनों देशों के 9 फेडरेशन की महिला प्रमुखों के साथ अन्य प्रतिनिधि भी जयपुर पहुंचे। ये महिला प्रतिनिधि धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर एवं उदयपुर में राजीविका समूहों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और राजस्थान विजिट के दौरान मुर्गीपालन, बकरीपालन, नैचुरल फार्मिंग, बायोगैस सहित अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। राजस्थान में बाजरा उत्पादन के लिए जैसा क्लाइमेट है वैसा ही इन अफ्रीकी देशों में भी है। फेडरेशन की महिला प्रमुख प्रशिक्षण के दौरान बाजरा उत्पादन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **माली और सेनेगल की 12,500 महिलाओं को राजीविका मॉडल की बदौलत रोजगार मिला**
- **धौलपुर की राजीविका मॉडल से जुड़ी महिलाओं ने माली और सेनेगल जाकर वहां की महिलाओं को सैल्फ हैल्फ ग्रुप, ग्राम संगठन और फैडरेशन बनाने का प्रशिक्षण दिया था, अब यहां की महिलाएं 17 करोड़ रू. की सालाना बचत कर कर्ज देकर अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं।**

पश्चिमी अफ्रीकी देश, माली और सेनेगल से महिलाओं के 9 फैडरेशनों की महिला प्रमुखों ने जयपुर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार से मुलाकात की। ये महिलाएं राजीविका मॉडल के प्रशिक्षण के लिए धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर एवं उदयपुर जाएंगी।

मु.मंत्री ने सरिस्का में 4 शावकों के जन्म पर खुशी जताई

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में 4 नए शावकों के जन्म के साथ बाघों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों एवं वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, नये शावकों के

- **सरिस्का अभयारण्य में बाघिन एस-22 ने चार शावकों को जन्म दिया है, अब सरिस्का में 40 बाघ हो गए हैं।**

जन्म से सरिस्का में अब बाघों की संख्या 40 हो गई है। हमारी सरकार बाघों के संरक्षण, संवर्धन सहित उनके अस्तित्व के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु संकल्पबद्ध है। उल्लेखनीय है कि, सरिस्का टाइगर रिज़र्व में बाघिन एसटी-22 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही बाघिन एसटी-12 का भी चौथा शावक कैमरे में कैद हुआ है। इससे पहले मार्च में उसके तीन शावक एक साथ देखे गए थे।